28

श्री नवाब सिंह चौहान : कुछ ग्रखबारों में निकला है कि मथुरा की रिफाइनरी को वहां से हटा कर इटावा पहुंचा दिया जाय क्योंकि उस के वहां रखने से ताज को खतरा है । क्या सरकार इस को इटावा पहंचाने का इरादा रखती है ?

SHRI H. N. BAHUGUNA: That question does not arise but there is a lot of public debate and fear in the minds of the people about this particular question. Therefore may inform the hon. Member that the report of the Expert Committee on Environmental Impact of Mathura Refinery was received a few days also and it is being examined. As soon we come to a conclusion on that we will come to the House and inform the House and we may assure the House that we will see that nothing hampers or mars of jeopardises Taj in any manner.

PROF. P. G. MAVALANKAR: entirely agree with the hon. Minister that this question has to be looked at the national interest; the location may be Gujarat, Assam or anywhere. In view of the fact that around Gujarat, Cambay, etc., and also in Bombay High the latest findings are that oil is coming in abundance and will be so available for many years come, there will be need for a refinery in Gujarat or near about Gujarat. In view of this may I ask him whether proposals for an additional refinery as well as petro-chemical complex are being discussed here by the officials of the Gujarat Government? They came to Delhi on the same aircraft with me yesterday for a discussion with the Planning Commission of the Gujarat plan. Are these proposals being actively considered by this Ministry in consultation with Planning Commission and the Gujarat Administration?

SHRI H. N. BAHUGUNA: hon. Members has raised a question which is in two parts: one is whether the state government of Gujarat has taken up any proposals regarding various types of industries connected with the Bombay High gas or petroleum. The second part is whether we are in touch with them or doing something about the whole thing. I may assure the hon. Member that we have constituted a working group for utilisation of the gas and oil from Bombay High and other regions. is a bilateral group, that is, ministry of petroleum and chemicals, Government of India, Planning Commission and the Government of Gujarat, their representatives. The details feasibility possibility for future set up, etc., are being worked. whole matter is under discussion and the working group is yet to come out with its final views about the whole matter.

श्री उप सेन : मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हं-क्या मथरा रिफाइनरी के बारे में उन के पास जो रिपोर्ट ग्राई है उस में इटली की एक टैक्नोकेट कम्पनी भौर हिन्दुस्तान के एक प्रमख वैज्ञानिक ने ऐसा लिखा है कि इस में सल्फर-भ्राक्साइड निकलता है जिस से ताज के सफेद ग्रीर लाल पत्थरों पर प्रभाव पडेगा इस लिये इस को वहां से हटा देना चाहिये। क्या यह भी उस रिपोर्ट में शामिल है ?

SHRI H. N. BAHUGUNA: I not willing to disclose the contents of the report except to say, as I have said earlier that this government will not let the interest of Taj suffer in any manner.

288 'बांच' लाइनीं का विस्तार

* 495. डा० महादीपक सिंह ज्ञाक्यः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने 288 द्रांच लाइनों के विस्तार के बारे में योजना आयोग से रिपोर्ट मांगी है; स्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) ः (क) जी नहीं।

(ख) प्रक्न नहीं उठता ।

डा० महादोषक सिंह शाक्य: ग्रन्थक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—इस पालियामेन्ट के प्रथम ग्रधिवेशन से इन 288 बांच लाइनों का मामला प्लानिंग कमीशन के पास चल रहा है— इस लिए प्लानिंग कमीशन से यह रिपोर्ट कब तक श्रा जायगी ?

प्रो० मजुदण्डवते : मूल प्रश्न में पूछा गया है कि इन 288 बांच लाइनों के बारे में रेलवे मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट मंगवाई है— मैंने उत्तर दिया है कि हम लोगों ने ऐसी रिपोर्ट नहीं मंगवाई है । लेकिन मैं ग्राप का बतलाना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो स्टडी-ग्रुप मुकरिंर किया गया है, उस में रेजवे के डवेल मेण्ट, कंस्ट्रक्शन ग्रीर नई लाइन्ज से सम्बन्धित प्रक्तों के बारे में विचार चल रहा है । हमारी श्रपेक्षा है कि दिसम्बर महीने में उनकी अन्तरिम रिपोर्ट हम लोगों के पास ग्रायेगी, उस से पता लग जायगा कि कितनी एलोकेशन रहेगी ग्रीर हालत क्या रहेगी।

लेकिन उन्होंने जो जिक्क किया है 208 लाइनों का, 288 नहीं, वे जो ब्रान्च लाइनें हैं ऐसी जान्च लाइनें की डैफीनी क्षन 1969 में इस तरह से की गई है। एक तो जो लाइन किसी भी गेज की हो, वह मैन लाइन को जोड़ी जाती है या किसी प्रकार की नेरो गेज लाइन, जहां ट्रांशिपमेंट की जरूरत होती है उस को ब्रान्च लाइन समझा जाता है। ऐसी जो ब्रान्च लाइन है इनमें हमें काफ़ी घाटा आ रहा है लेकिन वह एक अलग सवाल है।

डा० महादीपक सिंह शाक्य: मंत्री महोदय ने 288 ब्रान्च लाइनों के बारे में प्रभी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ब्रान्च लाइनों को मैन लाइनों से मिलाने के बारे में विचार चन रहा हैं। एटा से टुण्डला ब्रान्च लाइन हमेशा से घाटे में चल रही है, और सन् 1971 से अब तक इस हाउस में इस प्रश्न को लाया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि उस लाइन को फारूखाबाद मैन ब्रान्च लाइन से मिला दिया जाएगा?

प्रो० मधु दण्डवते: जैसा दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था कि हम लोगों के सामने आर्थिक किटनाई होने की वजह से, जो लाइने हमारे हाथ में हैं चाहे न्यू लाइनें हों या कोई कन्दर्जन का काम हो, उस काम को पहले पूरा करेंगे ग्रंगर उस के वाद दूसरी लाइनों को लेने के बारे में विचार करेंगे।

श्री रामपूर्ति: ग्रध्यक्ष महोदय, भारतवर्षे में हजारों मील लम्बी मीटर गेज की लाड़नें बिछी हुई हैं ग्रीर लाखों पेसेन्जर्स रोज एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते हैं ग्रीर हजारों टन माल उन से पहुंचाया जाता है। मेरा एक स्पेसीफिक प्रश्न यह है कि बजाए योजना पर लाखों रुपंये का खर्च करने के, इस धन को, रोड़ डेवलपमेंट ग्रीर ग्रामी क्षेत्रों के विकास पर क्यों नहीं लगाया जाता ग्रीर मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने का काम क्यों नहीं बन्द किया जाता।

प्रो० मधु वस्पवते : मान्यवर, एक तरफ़ तो पिछड़े हुए हत्कों में नई रेलवे लाइनों को बनाने के लिए कहा जाता है और उन की मांग की जाती है और दूसरी तरफ़ यह कहा जाता हैं कि जब इस तरह की लाइनों पर घाटा होता है, तो ऐसी स्कीमों को रह किया जाय और उस पैसे को रोड और

32

रूरल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए भीर उन पर ज्यादा घ्यान दिया जाए। इन दोनों विचारों को घ्यान में रख कर हम फैसला लेंगे।

श्री श्रोम प्रकाश त्यागी: नई लाइनों के विछाने या त्रान्च लाइनों को मैन लाइनों से जोड़ने के लिए श्राप ने कौन सा काइटीरया निश्चय किया है जिस की वेसिस पर श्राप यह निश्चय करते हैं कि यहां नई लाइन बननी चाहिए या केवल घाटे का प्रश्न ही श्राप के सामने है। कोई श्रीर काइटीरिया भी श्राप ने बना रखा है?

प्रो० मधु वण्डवते : ग्रगर रेलवे लाइन पिछड़े हल्कों में बननी हैं तो वहां कम से कम ट्रैंपिक की ग्रन्छी डेसिटी तो होनी चाहिए । यातायात की सुविधाएं बढ़ाने के लिए और ज्यादा लाइनें बिछाने के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब रिटन ज्यादा मिल सकता हो । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1972-73 से 1975-76 तक हमारी कितनी हैं ग्रान्च लाइनें थीं और उन पर कितना घाटा हुआ है :—

सन्	ग्राच लाइनें	घाटा करोड़ स्पये
1972-73	127	11.39
1973-74	139	19.90
1974-75	142	26.14
1975-76	132	25.75

इन सब बातों को व्यान में रख कर हम कोई फ़ैसला लेंगे।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Before opening more branch lines, will the minister tell us how many accidents are taking place per day on the railways and whether he will to try to minimise the accidents?

MR. SPEAKER How does it arise out of this?

PROF. MADHU DANDAVATE: I would reply to it on an appropriate occasion when there is 2 question on railways.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over.

SOME HON. MEMBERS: Still there are two minutes.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:
The next question can be taken up.

MR. SPEAKER: No, there is no time for answering it.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*496. SHRI D. B. CHANDRE GOW-DA: Will the Minister of PETRO-LEUM AND CHEMICALS AND FER-TILIZERS be pleased to state:

- (a) what is the annual production of industrial alcohol in the country and what are the names of the companies/States who are its major producers;
- (b) what are the names of the industries which are its main consumers; and
- (c) what steps are bing taken to increase production of industrial alcohol in the country?